दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम

बनाम

स्वपन कुमार मित्रा और अन्य।

3 फ़रवरी 2006

[अरिजीत पसायत और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

सेवा कानून

अनुशासनात्मक कार्यवाही - तथ्यों की सराहना और साक्ष्य की पर्याप्तता/विश्वसनीयता - माना गया: जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी इनके तहत एकमात्र न्यायाधीश हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, इन मुद्दों को प्रचारित भी नहीं किया जा सकता, ध्यान नहीं दिया जा सकता है और नकारा भी नहीं जा सकता।

अनुशासनात्मक कार्यवाही - सेवा से निष्कासन की सजा - माना गया: डी इसे दोषी कर्मचारी को जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा, इससे उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और उसे सुनवाई के उचित अवसर से वंचित कर दिया जाएगा।

अनुशासनात्मक कार्यवाही-आपराधिक मामले में दोषमुक्ति-धारण का

प्रभाव: विभागीय कार्यवाही में, अपराधी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के बाद भी सेवा से हटाने का आदेश पारित किया जा सकता है

प्रतिवादी नं. 1 अपीलकर्ता-परिवहन निगम में बस चालक के रूप में कार्यरत था। एक दिन वह जिस बस को चला रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ यात्री घायल हो गए। राज्य सरकार द्वारा आदेशित घटना की जांच में, जहां दुर्घटना हुई थी, वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें दुर्घटना के साथ-साथ बस यात्रियों की मौत और चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया। विभागीय जांच में, जांच अधिकारी ने जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसमें दिए गए बयानों पर भरोसा किया और जिलाधिकारी के निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की। इन निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से हटाने का आदेश दिया। हालाँकि, उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में, उनके अपराध के निष्कर्ष के समर्थन में सबूतों की अपर्याप्तता के आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया था।

प्रतिवादी नं. 1 ने उनके निष्कासन को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की (i) अनुशासनात्मक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रख सकता और आपराधिक मामले में उसके बरी होने के बाद सेवा से

हटाने की सजा नहीं दे सकता; (ii) जांच अधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, वे न तो आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में थे और न ही उनकी प्रतियां उन्हें प्रदान की गईं।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना (1) जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और उनके द्वारा भरोसा किए गए अन्य संबद्ध दस्तावेजों की प्रतियां और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की गैर-उपलब्धता ने विभागीय कार्यवाही को दूषित कर दिया। इसे देखते हुए हटाने का आदेश निरस्त कर दिया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रतिवादी संख्या को उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए और उसके बाद उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उसे सेवा से हटाने के सवाल पर नए निष्कर्ष पर पहुँचें। (ii) चूंकि किसी आपराधिक कार्यवाही में सबूत की डिग्री विभागीय कार्यवाही की तुलना में अधिक होती है, आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक अधिकारियों के लिए किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने और सेवा से निष्कासन का जुर्माना लगाने में बाधा नहीं बन सकता है।

प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के संबंध में,

डिवीजन बेंच ने पाया कि केवल इसकी फोटोकॉपी जांच अधिकारी के समक्ष दायर की गई थी और इसे अस्वीकार्य साक्ष्य माना गया था। इसके अलावा, चूंकि जिला मजिस्ट्रेट की जांच नहीं की गई थी और किसी ने भी उनकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित नहीं की थी, इसलिए जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करना संभव नहीं था। यह भी माना गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर जांच किए गए गवाहों की गवाही पर भरोसा करके जांच अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया और यह पूरी तरह से अवैध, शून्य और विकृति की ओर ले जाने वाला था। यह भी माना गया कि चूंकि एफआईआर में तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का जिक्र नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी संख्या 1 को बरी किए बिना इस आपराधिक मामले और उसके परिणामों में अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया, एकल न्यायाधीश के फैसले के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 1 की सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया, और अपीलकर्ता को उसे पूर्ण वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया और एक विशेष तिथि से निलंबन भत्ता. इसलिए वर्तमान कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित 1. एकल न्यायाधीश द्वारा मामले को अनुशासनात्मक

प्राधिकारी को वापस भेजने और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति और प्रतिवादी नंबर 1 और उसके बाद उसके द्वारा भरोसा किए गए अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति करने का आदेश देना उचित था । प्रतिवादी नंबर 1 से उन रिपोर्टों पर टिप्पणियां मांगने के बाद नए निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अपीलीय चरण में, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी नंबर 1 को सेवा से हटाने के सवाल पर गुण-दोष में जाकर प्रक्रिया को छोटा करना उचित नहीं माना खासकर जब एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी नंबर 1 के मामले का फैसला नहीं किया हो। योग्यता के आधार पर हटाने का प्रश्न और जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने व्यावहारिक रूप से जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हटाने का आदेश पारित किया था, जिसकी एक प्रति टिप्पणी दर्ज करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान नहीं की गई थी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों के एकमात्र न्यायाधीश हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता और विश्वसनीयता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कला के तहत रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचारित किया जा सके। संविधान के 226. बी सी [42-जी-एच: 43-ए-बी]

ए.पी. राज्य और अन्य। बनाम एस. श्री रामाराव, एआईआर (1963) एससी 1723; एयर इंडिया लिड बनाम एम. योगेश्वर राज, (2000) 5 467 और बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य का हवाला दिया गया।

2. दोषी कर्मचारी को सेवा से हटाने की सजा का आदेश जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि दोषी कर्मचारी को सेवा से हटाने के लिए जिन दस्तावेज़ों पर अधिकारियों द्वारा भरोसा किया गया था, वे दस्तावेज़ उसे उपलब्ध नहीं कराए गए तो उसके साथ गंभीर पूर्वाग्रह हो सकता है। इससे उसे सुनवाई के उचित अवसर से वंचित कर दिया जाएगा।

भारत संघ बनाम मोहम्मद रमज़ान खान, [1991] 1 एससीसी 588 और प्रबंध निदेशक ईसीआईएल हैदराबाद वी. बी. करुणाकर और अन्य, [1993] 4 एससीसी 727, इसके बाद।

देबोतोष पाल चौधरी बनाम. पंजाब नेशनल बैंक और अन्य. [2002] 8 एससीसी 68, संदर्भित.

3. किसी आपराधिक मामले में अपराधी कर्मचारी के बरी होने के बाद भी विभागीय कार्यवाही से सेवा से हटाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यह मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं है [38-डी; 37-एफ)

नेल्सन मोटिस बनाम भारत संघ और अन्य, [1992] 4 एससीसी 711 और सीनियर दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम स्वपन कुमार मित्रा (तरुणचट्टरी 33)

अधीक्षक डाकघर, पथमथिट्टा और अन्य। वी. ए. गोपालन, [1997] 11 एससीसी 239, दोहराया गया।

4. डिवीजन बेंच का यह निष्कर्ष गलत था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दोषी को सेवा से हटाने का आदेश विकृत था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्टों और उनके समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी नंबर 1 की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई और इसके परिणामस्वरूप 15 लोगों की जान चली गई और कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न करने के लिए, वैध रूप से यह माना जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का ऐसा निष्कर्ष विकृत प्रकृति का था। [44-जी; 45-बी, सी)

रोशन दी हट्टी बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली, [1977] 2 एससीसी 378, प्रतिष्ठित।

कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त। (1999) 2 सीसी 10, आयोजित अनुपयुक्त.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2005 की सिविल अपील संख्या 1015।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 26.8.2003 के निर्णय एवं आदेश से एफ.एम.ए. क्रमांक 292/2003.

अपीलकर्ताओं के लिए जनरंजन दास और श्वेतकेतु मिश्रा।

चंचल कुमार गांगुली, कु. आरती खेड़ा और वी.के. मोंगा के लिए उत्तरदाताओं.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

तरूण चटर्जी, जे. श्री सपन कुमार मित्रा, जो इस अपील में प्रतिवादी नंबर 1 हैं, को अपीलकर्ता, दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (संक्षेप में निगम) द्वारा बस चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। 21 अप्रैल 1994 को वह बस जिसे प्रतिवादी संख्या मैं चला रहा था, दुर्गापुर से मालदा के लिए रवाना हुई। 22 अप्रैल 1994 के शुरुआती घंटों में, यानी दिन में लगभग 00:30 बजे, बस फरक्का बैराज पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और खाड़ी में गिर गई। दुर्घटना तब हुई जब एक ट्रक बैराज पर विपरीत दिशा से बस के पास आया और जब पाया कि ट्रक विपरीत दिशा से बस के पास आ रहा है, तो बस चालक ने बस को तेजी से बाईं ओर मोड़ दिया और परिणामस्वरूप, यह बैराज के लॉक-गेट और रेलिंग से जा टकराया, जिससे, बस गिर गई।

इस दुर्घटना के कारण 15 अनमोल जानें चली गईं और कई अन्य

यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ एक विभागीय जांच के साथ-साथ एक आपराधिक कार्यवाही भी शुरू की गई थी। आपराधिक कार्यवाही बस यात्रियों में से एक के कहने पर की गई थी जो घायल हो गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह आपराधिक मामला 1994 के फरक्का पुलिस केस नंबर 34 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 427 और 301 ए के तहत दर्ज किया गया था। उसी समय प्रतिवादी संख्या 1. बी के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की गई जहां तक आपराधिक मामले का सवाल है,

यह प्रतिवादी संख्या 1 को इस आधार पर बरी करने के साथ समाप्त हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अदालत के पास पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं थे।

जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, 22 अप्रैल 1994 को हुई घटना की विभागीय जांच के बाद प्रतिवादी नंबर । को सेवा से हटा दिया गया था, जिसमें 15 बस यात्रियों की मौत हो गई थी और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे: जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को यह जांच करने का निर्देश दिया कि इस दुर्घटना और 15 यात्रियों की मौत और अन्य बस यात्रियों के घायल होने के लिए कौन जिम्मेदार है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को

जिम्मेदार ठहराते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, उनके द्वारा दिए गए बयानों और जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए बयानों पर विचार करते हुए, जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी नंबर । ने अपनी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का कारण बना, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। 15 व्यक्ति एफ और अन्य बस यात्रियों को भी गंभीर चोटें आईं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी संख्या । को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया। हटाने के आदेश को प्रतिवादी संख्या 1 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि यद्यपि प्रतिवादी नंबर 1 के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए एक वैधानिक अपील उपलब्ध थी, लेकिन उसने निष्कासन के आदेश को चुनौती देने के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। सेवा से हटाने के आदेश को प्रतिवादी नंबर 1 ने मुख्य रूप से दो आधारों पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

पहला आधार जिस पर हटाने के आदेश को खराब और एच कानून में अमान्य कहा गया था, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में

बिल्कुल भी सुविधा नहीं है और न ही उनकी कोई प्रतियां प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान की गईं, ऐसे दस्तावेजों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 को सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। चुनौती का दूसरा आधार यह था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था और आपराधिक मामले में बरी होने के बाद प्रतिवादी नंबर । के खिलाफ सेवा से निष्कासन की सजा नहीं दे सकता था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले आधार अर्थात् जिले की रिपोर्ट की प्रतियों की आपूर्ति न करने को सही ठहराया है। मजिस्ट्रेट एवं उनके द्वारा जिन अन्य संबद्ध दस्तावेजों पर भरोसा किया गया तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट विभागीय कार्यवाही को निष्फल करती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह भी माना गया था कि चूंकि आपराधिक कार्यवाही में सबूत की डिग्री विभागीय कार्यवाही की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का अनुकरण करने में बाधा नहीं बन सकता है। कर्मचारी, यानी प्रतिवादी नंबर 1 या उसी के साथ आगे बढ़ने और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने से, हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कासन के आदेश को रद्द करना उचित समझा और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आपूर्ति करने का निर्देश दिया।

यहां पहले उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां, प्रतिवादी नंबर 1 को उक्त दस्तावेजों के खिलाफ टिप्पणियां दाखिल करने के लिए और उसके बाद उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 को सेवा से हटाने के प्रश्न पर नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, अंतिम आदेश निम्नलिखित तरीके से पारित किया गया: -

> परिणामस्वरूप, रिट याचिका आंशिक रूप से सफल हो जाती है। रिट याचिका के पृष्ठ 46 पर प्रदर्शित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता को उन दस्तावेजों की प्रतियां मांगने की स्वतंत्रता दी गई है जो वह वर्तमान कार्यवाही के उद्देश्य से चाहता है। ऐसा अनुरोध प्रतिवादी प्राधिकारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को कल तक किया जाना चाहिए। प्रतिवादी प्राधिकारी इसके बाद तीन दिनों के भीतर इसकी प्रतियां प्रस्तुत करेगा। रिट याचिकाकर्ता उक्त दस्तावेजों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी टिप्पणियाँ देने का हकदार होगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस तरह का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अंतिम आदेश पारित करेगा और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देगा।

कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण यथाशीघ्र दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना होगा यदि स्पष्टीकरण की पेशकश की जाती है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी एक अंतिम आदेश पारित करेगा और उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर उसे सूचित करेगा।

रिट याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा मामले का अंतिम निर्णय होने तक निलंबित माना जाता है।

अंतिम आदेश पारित करते समय अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय बकाया वेतन और/या निर्वाह भत्ते के मुद्दे पर भी निर्णय लेगा।

रिट याचिका को कॉस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के तदनुसार निपटाया जाता है"

व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय, उच्च न्यायालय डी की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी। हालाँकि, अपील में डिवीजन बेंच ने यह नहीं कहा कि आपराधिक मामले में बरी होने के बाद विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती और इस प्रकार अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निष्कासन का कोई आदेश पारित नहीं

किया जा सका। लेकिन डिविजन बेंच ने यह माना कि क्या अपराधी ने पूछा था क्योंकि जांच अधिकारी के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों की प्रतियों पर भरोसा किया गया था वे बिल्कुल भी वास्तविक नहीं थीं। डिवीजन बेंच के अनुसार, जब तक किसी दस्तावेज़ को आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक उसका उपयोग अपराधी को पर्याप्त अवसर दिए बिना और उस पर भरोसा करने के लिए छुट्टी प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। चूंकि इसका पालन नहीं किया गया, डिवीजन बेंच के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वयं रद्द किये जाने योग्य था। इस समय, हम खुद को याद दिला सकते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना था कि प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान नहीं किए गए दस्तावेजों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे और प्रतिवादी नंबर 1 को ऐसे दस्तावेज़ों के विरुद्ध अभ्यावेदन और/या टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। यही कारण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रतिवादी नंबर 1 को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने, प्रतिवादी को अनुमति देने का निर्देश दिया। जी नंबर 1 को अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करनी होंगी और फिर प्रतिवादी नंबर । की निष्पक्ष सुनवाई के बाद यहां पहले संदर्भित मुद्दे पर नए और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि, चूंकि जिला मजिस्ट्रेट की जांच नहीं

की गई थी और किसी ने भी उसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता साबित नहीं की थी, इसलिए जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी एच के लिए उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करना संभव नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट के आधार पर ए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया। डिवीजन बेंच ने यह मानते हुए एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला था कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट बनाने में ऐसे गवाहों की जांच किए बिना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कथित तौर पर जांच किए गए गवाहों के बयानों पर भरोसा करके अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया था। तदनुसार, डिवीजन बेंच ने माना कि इस तरह की गवाही पर निर्भरता पूरी तरह से अवैध और शून्य है, जिससे विकृति पैदा होती है। इसके बाद, डिवीजन बेंच ने एफआईआर सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में प्रतिवादी नंबर 1 की लापरवाही से गाड़ी चलाने का उल्लेख न करने के तथ्य पर भी विचार किया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई, खंडपीठ ने कहा कि चूंकि एफआईआर में तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का जिक्र नहीं है, इसलिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बेंच का यह भी निष्कर्ष था कि चूंकि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की केवल एक जेरॉक्स कॉपी जांच अधिकारी के समक्ष दायर की गई थी, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की ऐसी जेरॉक्स कॉपी साक्ष्य में अस्वीकार्य थी। उपरोक्त निष्कर्षों पर, डिवीजन बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के

साथ-साथ जांच अधिकारी के निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत थे। तदनुसार, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और प्रतिवादी नंबर 1 को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया था और निगम को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी नंबर 1 को एक विशेष तारीख से पूर्ण बकाया वेतन और निलंबन भत्ते के साथ बहाल करे।

डिवीजन बेंच के इस अंतिम आदेश के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 को हटाने और बहाल करने के आदेश को रद्द करते हुए, यह अपील निगम द्वारा दायर की गई है और इसे अनुमति के बाद पार्टियों के विद्वान वकील की उपस्थिति में सुना गया था।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और इस मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड की भी जांच की है। हालाँकि डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था कि विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है और जब आपराधिक मामला बरी हो जाता है तो दोषी कर्मचारी को सजा नहीं दी जा सकती है, फिर भी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने हमारे सामने इस आधार पर बहस करने की मांग की। हमारे विचार में, यह मैदान अब पुनः एकीकृत नहीं है। नेल्सन मोटिस बनाम भारत संघ और अन्य, [1992] 4 एससीसी 711 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 5 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"अब तक पहले बिंदु का सवाल है, कि क्या आपराधिक

मामले में अपीलकर्ता के बरी होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखी जा सकती थी, इस दलील में कोई दम नहीं है जो भी हो और विस्तृत विचार के योग्य नहीं है। किसी आपराधिक मामले की प्रकृति और दायरा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से बहुत अलग होता है और इसलिए बरी करने का आदेश विभागीय कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने बताया है कि जिन कृत्यों के कारण विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई, वे बिल्कुल वही नहीं थे जो आपराधिक मामले का विषय थे।"

(जोर दिया गया)

इसी तरह वरिष्ठ डाक अधीक्षक अधिकारी, पथमथिट्टा और अन्य। वी. ए. गोपालन, [1997] 11 एससीसी 239 नेलासन मोटिस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में व्यक्त विचार। (सुप्रा) का इस न्यायालय और सी द्वारा पूरी तरह से समर्थन किया गया था, इसी तरह यह माना गया था कि एक आपराधिक मामले में सबूत की प्रकृति और दायरा एक विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से बहुत अलग है और पूर्व में बरी करने के आदेश से विभागीय कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती है। इस न्यायालय ने आगे कहा है

कि एक आपराधिक मामले में आरोप को उचित संदेह से परे सबूत द्वारा साबित किया जाना चाहिए, जबकि विभागीय कार्यवाही में आरोप साबित करने के लिए सबूत का मानक केवल संभावनाओं की प्रबलता है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, जिनमें से दो का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, द्वारा तय की गई कानून की स्थिति ऐसी है, हमें इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किसी आपराधिक मामले में बरी होने पर यह माना जाएगा कि विभागीय कार्यवाही भी होनी चाहिए बंद किया जाए. ऐसी स्थिति में, विभागीय कार्यवाही ई से उत्पन्न होने वाली सेवा से निष्कासन का आदेश किसी आपराधिक मामले में दोषी कर्मचारी के बरी होने के बाद भी पारित किया जा सकता है। किसी भी मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश और साथ ही डिवीजन बेंच ने इस प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए अपने फैसले नहीं लिए कि आपराधिक मामले में बरी होने के बाद विभागीय कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है और निष्कासन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

इस सवाल पर कि क्या जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां सेवा से हटाने का कोई भी आदेश पारित करने से पहले, प्रतिवादी संख्या 1 को दी

जानी चाहिए। यह निस्संदेह सच है कि प्रतिवादी नंबर 1 को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान किए बिना सजा का ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, विभागीय कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर देगी और बहाली के लिए निर्देश पारित किए जाने चाहिए या अधिकारियों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 को सेवा में इस शर्त पर सीधे बहाल किया जाना चाहिए एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी दस्तावेजों की प्रतियां आपूर्ति करने के चरण से अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखी जावें तथा नये और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। यह इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 1 पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि उसे सेवा से हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे उसे सुनवाई के उचित अवसर से वंचित होना पड़ेगा। यह विचार भारत संघ बनाम मोहम्मद रमज़ान खान [1991] । एससीसी 588 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा भी व्यक्त किया गया था, जिसे प्रबंध निदेशक ईसीआईएल हैदराबाद और अन्य बनाम बी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। करुणाकर और अन्य,

[1993] 4 एससीसी 727। इस न्यायालय ने रमज़ान खान के मामले (सुप्रा) में अनुच्छेद 18 में स्पष्ट रूप से निम्नानुसार देखा है:

> "जहां भी कोई जांच अधिकारी रहा है और उसने जांच के निष्कर्ष पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें अपराधी को सभी या किसी भी आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है और किसी विशेष सजा या नहीं के प्रस्ताव के साथ, अपराधी एक का हकदार है ऐसी रिपोर्ट की प्रति और अगर वह चाहे तो इसके खिलाफ अभ्यावेदन देने का भी हकदार होगा, और रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन होगा और अंतिम आदेश को इसके बाद चुनौती दी जा सकती है।"
>
> (जोर दिया गया)

जैसा कि उल्लेख किया गया है, इस निर्णय को प्रबंध निदेशक ईसीआईवी हैदराबाद और अन्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। वी. बी. करुणाकर और अन्य, [1993] 1 एससीसी 727। संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना है कि किसी दोषी कर्मचारी को हटाने की सजा देने के लिए, उसे जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक है। दंड अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाया जाता है। जांच रिपोर्ट न देने के मुद्दे पर संविधान पीठ ने इस प्रकार

टिप्पणी की:

"जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार को पहले चरण में उचित अवसर का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है और यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाते हैं।

प्राधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्यों के साथ-साथ उन पर भी विचार करता है। पहले से यह कहना मुश्किल है कि रिपोर्ट में अनुशंसित दंड सहित उक्त निष्कर्षों का विस्तार, यदि कोई हो, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किस हद तक प्रभावित करेगा। इसके निष्कर्ष। आगे के निष्कर्षों को रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सबूतों पर विचार किए बिना, या इसे गलत तरीके से या इसके द्वारा समर्थित नहीं करके दर्ज किया गया हो सकता है। यदि ऐसा निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले दस्तावेजों में से एक है, तो प्राकृतिक के सिद्धांत न्याय की आवश्यकता है कि निंदा किए जाने से पहले नियोक्ता को मिलने, समझाने और उसे बदलने का उचित अवसर मिलना चाहिए। यह न्याय के सिद्धांतों की उपेक्षा है और कर्मचारी

को जवाब देने का अवसर दिए बिना जांच अधिकारी जैसे तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करना कर्मचारी को उचित अवसर से वंचित करना है। यद्यपि यह सत्य है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच में दर्ज साक्ष्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए, यह भी उतना ही सत्य है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी साक्ष्यों के साथ-साथ जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भी विचार करता है। इन परिस्थितियों में, जांच अधिकारी के निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष एक महत्वपूर्ण सामग्री का गठन करते हैं जो इसके निष्कर्षों को प्रभावित करने की संभावना है। यदि जांच अधिकारी को केवल साक्ष्य रिकॉर्ड करना था और उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अग्रेषित करना था, तो इससे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं बनेगी जिसके बारे में दोषी कर्मचारी को कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि, जब जाँच अधिकारी आगे बढ़ता है और अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी, या उसके विपरीत हो सकता है या उससे अनभिज्ञ हो सकता है। इस तरह के निष्कर्ष कर्मचारी के

लिए अज्ञात अतिरिक्त सामग्री हैं, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचते समय इस पर विचार करते हैं। इसलिए, उचित अवसर के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, दोषी कर्मचारी को जांच अधिकारी के निष्कर्षों का जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी को साक्ष्य, जांच अधिकारी की रिपोर्ट और उसके खिलाफ कर्मचारी के प्रतिनिधित्व पर विचार करना आवश्यक है।"

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, इसलिए, हमारे पास कोई विवाद नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और सभी संबद्ध दस्तावेजों की एक प्रति का हकदार था। , जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरोसा किए गए गवाहों के बयान भी शामिल हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 को इन दस्तावेज़ों की प्रतियां न देने का क्या प्रभाव होना चाहिए? क्या न्यायालय के पास हटाने के आदेश को रद्द करने, विभागीय कार्यवाही को

रद्द करने और यांत्रिक रूप से इस आधार पर बहाली का आदेश देने का अधिकार था कि दस्तावेजों की प्रतियां, यहां पहले संदर्भित, प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान नहीं की गई थीं या एक निर्देश दिया गया था अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दें, जैसा कि विद्वान एच एकल न्यायाधीश द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए किया गया था और फिर अपराधी को अनुमति दी गई थी कर्मचारी को एक अभ्यावेदन देना होगा या उस पर एक टिप्पणी दर्ज करनी होगी और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 की सेवा से हटाने के सवाल पर उसके द्वारा की गई टिप्पणियों और पूछताछ रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष रखे गए पर विचार करने के बाद एक नए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उस चरण से आगे बढ़ना होगा। प्रबंध निदेशक ईसीआईएल (सुप्रा) के मामले में इस पहलू को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी ध्यान में रखा गया था और इसे निम्नानुसार माना गया था:

> "अगला प्रश्न यह है कि जब जांच अधिकारी की रिपोर्ट कर्मचारी को नहीं दी जाती है तो सजा के आदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में उसे क्या राहत दी जानी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर दी गई सज़ा के सापेक्ष होना चाहिए । जब कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा से हटा दिया जाता है और जांच रद्द कर दी जाती है

क्योंकि रिपोर्ट उसे प्रस्तुत नहीं की गई है, तो कुछ मामलों में रिपोर्ट न प्रस्तुत करने से उस पर गंभीर पूर्वाग्रह हो सकता है जबकि अन्य मामलों में यह हो सकता है कि उसे दी गई अंतिम सजा पर कोई फर्क न पड़ा हो। इसलिए सभी मामलों में बकाया वेतन के साथ कर्मचारी की बहाली का निर्देश देना न्याय के नियमों को एक यांत्रिक अनुष्ठान में बदल देना है। उचित अवसर का सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कानून के शासन को बनाए रखने और व्यक्ति को उसके न्यायिक अधिकारों की पुष्टि करने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। वे न तो मंत्रों का प्रयोग करते हैं और न ही सभी और विविध अवसरों पर किए जाने वाले संस्कार हैं। क्या वास्तव में, रिपोर्ट को अस्वीकार करने के कारण नहीं, कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, जहां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी, कोई अलग परिणाम नहीं हुआ होगा, कर्मचारी को ड्यूटी पर फिर से शुरू करने और सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना न्याय का उल्लंघन होगा। यह बेईमानों और दोषियों को पुरस्कृत करने के समान है और इस प्रकार, न्याय की अवधारणा को

अतार्किक और अपमानजनक सीमाओं तक खींच रहा है। यह "प्राकृतिक न्याय का अप्राकृतिक विस्तार" है जो अपने आप में न्याय के विपरीत है।

इसलिए, उन सभी मामलों में जहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी कर्मचारी को प्रस्तुत नहीं की जाती है, अदालतों और न्यायाधिकरणों को रिपोर्ट की प्रति पीड़ित कर्मचारी को प्रदान करनी चाहिए, यदि उसने पहले से ही सुरक्षित नहीं की है (आने से पहले 1) न्यायालय/न्यायाधिकरण को, और कर्मचारी को यह दिखाने का अवसर दें कि रिपोर्ट की आपूर्ति न होने के कारण उसके मामले पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यदि पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिपोर्ट न देने से अंतिम निष्कर्षों और दी गई सजा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट/ट्रिब्यूनल को सजा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट/ट्रिब्यूनल को सजा के आदेश को इस आधार पर स्वचालित रूप से रद्द नहीं करना चाहिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जैसा कि अफसोस की बात है कि वर्तमान में किया जा रहा है। अदालतों को शॉर्ट-कट का सहारा लेने से बचना चाहिए। चूंकि यह

अदालतें/न्यायाधिकरण हैं जो प्रश्न पर अपना न्यायिक मस्तिष्क लगाएंगे और जो कि सजा के आदेश को रद्द करने या रद्द न करने के लिए अपने कारण बतायेगें, (और कोई आंतरिक अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी नहीं), न तो कोई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और न ही उचित अवसर से इनकार। ऐसा तभी होता है जब अदालतों/न्यायाधिकरणों को लगता है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मामले के परिणाम में कोई फर्क पड़ेगा, तो उसे सजा के आदेश को रद्द कर देना चाहिए। जहां उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, न्यायालय/न्यायाधिकरण सजा के आदेश को रद्द कर देता है, उचित राहत जो दी जानी चाहिए वह है प्राधिकारी को स्वतंत्रता के साथ कर्मचारी की बहाली का निर्देश देना चाहिए। कर्मचारी को निलंबित करके और उसे रिपोर्ट देने के चरण से ही जांच जारी रखकर जांच आगे बढ़ाएगा। यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी की तारीख से अपनी बहाली की तारीख तक बकाया वेतन और अन्य लाभों का हकदार होगा, यदि अंततः आदेश दिया गया तो इसे कानून के अनुसार संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाना। कार्यवाही और अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। यदि

कर्मचारी नई जांच में सफल हो जाता है और उसे बहाल करने का निर्देश दिया जाता है, तो प्राधिकारी को कानून के अनुसार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि वह बर्खास्तगी की तारीख से बहाली तक की अवधि की गणना किस प्रकार की जायेगी, और वह किन लाभों का किस सीमा तक प्राप्त करने का हकदार होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जांच को रद्द करने के परिणामस्वरूप की गई बहाली को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण से नई जांच आयोजित करने के उद्देश्य से बहाली के रूप में माना जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं, जहां ऐसी नई जांच आयोजित की जाती है। कानून में भी यही सही स्थिति होगी" (जोर दिया गया)।

संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेजने और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के साथ जांच रिपोर्ट की एक प्रति और अन्य दस्तावेज प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान करने का आदेश देने पर भरोसा किया और उसके बाद उससे आगे बढ़ने के लिए भरोसा किया प्रतिवादी संख्या 1 से उन रिपोर्टों पर टिप्पणियाँ मांगने के बाद चरण एक नए निष्कर्ष पर पहुंचना उचित

ठहराया था। हमारा विचार है कि अपीलीय चरण में, डिवीजन बेंच को प्रतिवादी संख्या । की सेवा से हटाने के सवाल पर गुण-दोष में जाकर प्रक्रिया को छोटा करना उचित नहीं था, खासकर जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने फैसला नहीं किया था गुण-दोष के आधार पर हटाने के सवाल पर प्रतिवादी नंबर । की ओर से आया और जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने व्यवहारिक रूप से जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हटाने का आदेश पारित किया था, जिसकी एक प्रति टिप्पणी दर्ज करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान नहीं की गई थी। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों के एकमात्र न्यायाधीश हैं। साक्ष्य की पर्याप्तता और विश्वसनीयता ऐसा मामला नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचारित किया जा सकता है (देखें: ए.पी. राज्य और अन्य बनाम एस. श्री राम राव, एआईआर (1963) एससी 1723).

यह सच है कि रिपोर्ट की एक प्रति, जो जांच अधिकारी के समक्ष दायर की गई थी, प्रतिवादी नंबर 1 और उसके सहायक द्वारा जांच की गई थी और उसके बाद उन्होंने दस्तावेजों को स्वीकार कर लिया और जांच अधिकारी के सामने गवाही दी। यह भी सच है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के निरीक्षण के बाद न तो उनके सहायक और न ही प्रतिवादी नंबर । ने टिप्पणी दर्ज करने का अवसर मांगा और न ही रिपोर्ट के मूल न होने

के कारण इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति जताई। ऊपर दिए गए हमारे निष्कर्षों और निर्देशों के मद्देनजर इस स्तर पर इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। निगम की ओर से पेश हुए श्री दास ने आग्रह किया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया था, जिस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भरोसा किया गया था, इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। इस तर्क के समर्थन में टिप्पणियाँ दाखिल करने के लिए, [2002] 8 एससीसी 68 में रिपोर्ट किए गए देबोतोष पाल चौधरी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया गया था। संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर और ऊपर दिए गए हमारे निर्देशों के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अब जांच रिपोर्ट की एक प्रति और जांच अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति के बाद विभागीय कार्यवाही का निपटान करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न पर जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगा।

मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, जिन आधारों पर डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया था और हटाने के आदेश और विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 226 की पर्यवेक्षी शक्ति उनके अभ्यास में इसके लिए खुला नहीं था। विभागीय कार्यवाही को रद्द करने के

कई आधारों में से एक यह था कि चूंकि दस्तावेजों की सूची एक आरोप पत्र के साथ संलग्न हो, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया गया था, जिला मजिस्ट्रेट की उक्त रिपोर्ट पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी और इसलिए उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए जो निष्कासन आदेश पारित किया गया था, उसे अपास्त किए जाने योग्य था व बिना किसी अग्रिम जांच के बहाल किये जाने योग्य रखा जाए और आदेश दिया जाए इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, बहाली को बिना किसी और जांच के पारित किया जाना चाहिए। चूंकि जांच रिपोर्ट की मूल प्रति दाखिल नहीं की गई थी और केवल उसकी जेरॉक्स कॉपी दाखिल की गई थी, ऐसी जेरॉक्स कॉपी प्रतिवादी नंबर 1 को हटाने का आदेश पारित करने के उद्देश्य से विचार पर बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती थी। अब यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी या जांच अधिकारी न्यायालय नहीं हैं और इसलिए अदालतों में अपनाई जाने वाली सख्त प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। का कड़ाई से पालन किया गया। बी.सी.चतुर्वेदी बनाम भारत संघ सी एवं अन्य में। [1995] 6 एससीसी 749, इस अदालत द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि एक विभागीय कार्यवाही में, कानूनी सबूत के सख्त सबूत और उस सबूत पर निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, हमारे पहले दिए गए निर्देशों के मद्देनजर, यानी, जब दस्तावेजों की प्रतियां विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद कार्यवाही जारी रहेगी, तो डिवीजन

बेंच के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि इस मुद्दे पर निर्णय करें जैसा कि उसने गलत किया था।

फिर से इस सवाल पर कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार था, जिसके कारण 15 बस यात्रियों की मौत हो गई और कुछ अन्य को गंभीर चोटें आईं, ऊपर की गई हमारी चर्चाओं के मद्देनजर इस चरण पर, ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच ने एफ तथ्यों पर ऐसे प्रश्न का निर्णय करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश देने से पहले अपीलीय चरण में पहले बताए गए प्रश्न पर निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की थी। इसके अलावा, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश में बताए गए तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाही के नए सिरे से निपटान का निर्देश दिया था, तो हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच को प्रथम दृष्टया तथ्यों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को पहले से नहीं लेना चाहिए था। जांच के विषय पर निष्कर्ष निकालना जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपना मन बनाना था (देखें: एआईआर इंडिया लिमिटेड बनाम एम. योगेश्वर रुज। [2000] 5 एससीसी 467)।

एक और पहलू है जिस पर हमें इस फैसले पर पहुंचने से पहले विचार करना होगा। डिवीजन बेंच के आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं

कि डिवीजन बेंच ने यह भी पाया कि हटाने का आदेश पारित करने में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष विकृत थे। हम डिवीजन बेंच के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। रोशन दी हट्टी बनाम में आयकर आयुक्त, दिल्ली, [1977] 2 एससीसी 378, इस न्यायालय ने एक निष्कर्ष की विकृति के सवाल पर विचार करते हुए यह माना कि जब तथ्य का निष्कर्ष बिना किसी सामग्री के या तथ्यों को देखने के आधार पर निकाला गया हो उचित रूप से विचार नहीं किया गया या पाए गए तथ्य ऐसे थे कि न्यायिक रूप से काम करने वाला और संबंधित कानून के बारे में उचित निर्देश देने वाला कोई भी व्यक्ति उस निर्णय पर नहीं आया होगा, निर्णय को विकृत कहा जा सकता है। हालाँकि, यह सच है कि यदि विकृति दिखाई जाती है और साबित हो जाती है, तो रिट कोर्ट इसे वैसा ही मानने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन, हमारे विचार में, यह विकृत खोज का मामला नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्टों और उनके समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी नंबर 1 की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई थी। और इसके परिणामस्वरूप 15 लोगों की जान चली गई और कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच रिपोर्ट की आपूर्ति न करने पर, वैध रूप से यह माना जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का ऐसा निष्कर्ष विकृत प्रकृति का था। मामले

के किसी भी दृष्टिकोण में, जब विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रतियां प्रतिवादी नंबर 1 को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, और उसके बाद विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए डिवीजन बेंच के लिए हस्तक्षेप करने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। ऐसे आदेश के साथ और अपीलीय स्तर पर विभागीय कार्यवाही को रद्द करने और गुण-दोष पर जाकर मामले का फैसला करें।

कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, [1999] 2 एससीसी 10 में निर्णय, जैसा कि श्री गांगुली ने प्रतिवादी संख्या । के लिए उपस्थित होकर निष्कर्ष की विकृति के प्रश्न पर भरोसा किया था, हमारे विचार में, बिल्कुल भी लागू नहीं है। इसलिए, उनके हिसाब से भी, विकृति के सवाल पर डिवीजन बेंच के निष्कर्षों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।

हमने पहले ही संकेत दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रतिवादी नंबर 1 को जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति के चरण से आगे बढ़ने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित ठहराया था। अब हमारे सामने यह कहा गया है कि आदेश के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश, उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने भरोसा किया था, अपराधी कर्मचारी को प्रदान की गई हैं। भले ही ऐसे दस्तावेज़ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के

अनुसार प्रदान नहीं किए गए हों, फिर भी इस निर्णय की प्रति प्राप्त करने का आवदेन पेश करने से एक पखवाड़े की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या । को प्रदान किया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए यह खुला होगा कि वह मामले में किए गए निष्कर्षों के खिलाफ टिप्पणियां या अभ्यावेदन दायर कर सके। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सहित एक जांच रिपोर्ट। इन टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को इस सवाल पर नए और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्देश दिया जाता है कि क्या प्रतिवादी संख्या । को सेवा से हटाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रतिवादी संख्या । या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के लिए खुला होगा कि वह गवाहों से जिरह कर सके, और ज़ीरॉक्स कॉपी की स्वीकार्यता का प्रश्न भी उठा सके।अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का बी. तदनुसार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को यहां ऊपर किए गए संशोधनों के अधीन बहाल किया गया है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 को निगम के नियमों के अनुसार निर्वाह सी भत्ता का भुगतान किया जाएगा। ऊपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

कॉस्ट के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

वी.एस.एस.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा शर्मा (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।